मध्य प्रदेश में कृषिगत विकास के लिए धन

7682. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश सरकार को कृषि विकास हेतु कुल कितनी सहायता-राशि दी गई है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने गत वर्ष इस प्रयोजनार्थ और अधिक सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया था;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमंग) :

(क) योजना आयोग राज्यों के परामर्श से उनकी वार्षिक योजनाओं में विकास के विभिन्न क्षेत्रकों के लिए क्षेत्रकीय आवंटनों को अंतिम रूप देता है। पिछले 3 वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश राज्य हेतु कृषि और सम्बद्ध कार्यकलापों के लिए अनुमोदित परिव्यय हैं :

1993-94 -181.64 करोड़ रुपये

1994-95 - 185.05 करोड़ रुपये

1995-96 -213.83 करोड़ रुपये (प्रस्तावित)

(ख) योजना आयोग को मध्य प्रदेश सरकार से 1994-95 के दौरान अतिरिक्त धनराशि के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठते ।

Seperate cell to formulate plans for backward areas

7683. SHRI NYODEK YONGGAM: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether Government propose to consider the setting up of a separate cell to formulate plans for the backward areas in view of the growing demand for separate States and autonomous council on grounds of economic backwardness;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI GIRIDHAR GAMANG): (a) No, Sir. The planning and development of a backward area within a State is primarily the responsibility of the concerned State Government.

(b) & (c) do not arise.

District-wise schemes in Gujarat

7684. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) what are the district-wise details of various schemes for which Government have provided funds to Gujarat State and what is the amount provided for each schemes during the year 1994-95; and

(b) what are the criteria fixed for spending the said funds?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI GIRIDHAR GAMANG): (a) and (b) The Planning Commission approves the State Plan outlays for the State as a whole and not region or district-wise. The Anuual Plan outlay approved for Gujarat in 1994-95 is Rs. 2240 crores.